ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

मेरे बचपन का साइकिल वाला प्यार ले डूबा कोरोना

रविवारीय, 07 - 13 जून 2020 वर्ष- एक, अंक-44, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

आइये अपने हिस्से का पौधा लगाएं और उसे सींच कर पेड़ बनाएं :हेमन्त सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए कहा हम प्रकृति की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प लें। आइये प्रकृति का सम्मान करें। हम आने वाली पीढ़ी के लिए वनों से आच्छादित झारखण्ड का निर्माण करें। अपने हिस्से का पौधा लगाएं और उसे सींच कर पेड़ बनाएं।

कांके डैम से हटेगा अतिक्रमण ?

मनोज कुमार शर्मा

रांची : राजधानी की बड़ी आबादी को जलापूर्ति करने वाले कांके डैम (गोंदा जलाशय) को अतिक्रमणमुक्त करने का प्लान राज्य सरकार ने बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसमें संज्ञान लिया है। शहर में स्थित होने के कारण कांके डैम में बहुत ज्यादा अतिक्रमण है। ग्रीनलैंड तो दूर की चीज है यहां डैम के कैचमेंट जिसमें पानी रहता है उसे भी अतिक्रमित कर लिया गया है। अतिक्रमण करने वालों में रईस अमीर लोगों से लेकर गरीब और मजदूर सभी शामिल हैं। अब ये देखना होगा कि क्या सरकार सचमुच सख्ती से अतिक्रमण हटा कर रांची के इस जीवनदायिनी झील को बचाने में सफल होती है या ये सब सिर्फ दिखावे की कवायद भर है?

पहले भी एक बार कांके डैम के चारो ओर बने मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमणमुक्त कराया गया था, सरोवर नगर इलाके में तो पूर्व में ध्वस्त किये गये अवैध मकानों के अवशेष आज भी हैं। हाल के कुछ सालों में धीरे धीरे फिर से मकान बनते गये और वापस पुराने रूप में ही अतिक्रमण कर लिया गया। दुबारा हुये अतिक्रमण में तो कुछ इलाकों में और बड़े पक्के मकान बना लिये गये हैं।

कांके डैम का निर्माण 1956 में हुआ था और तब से लेकर आज तक में सिर्फ एक बार कुछ साल पहले छोटे हिस्से से गाद की सफाई हुई थी। ज्ञात हो कि एक बार सीसीएल ने कांके डैम से गाद के सफाई की पेशकश की थी, लेकिन तब बेतुकी सरकारी शर्तों के कारण सीसीएल ने अपने हाथ वापस खींच लिये थे। वर्तमान में रांची की पहचान रहा कांके डैम अतिक्रमण और प्रदूषण से त्रस्त है।

ग्रीन रिवोल्ट ने बार-बार कांके डैम के मुद्दे को उठाया है

ग्रीन रिवोल्ट ने अपने पहले अंक में ही कांके डैम के जलस्त्रोत की विलुप्ति पर खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद डैम में वाटर फिल्टर प्लांट बनाने के नाम पर दो लंबा पाइप खंभों पर बिछा दिया गया, हाल ही में देवी मंडपरोड में बने नालों की निकासी अंततः कांके डैम में ही कर दी गयी है। अवैध मिट्टी कटाई से लेकर सीमेंट या मकानों के अवशेष भी डंप करने का काम इसी के किनारे होता है।

जनप्रतिनिधियों के वोट बैंक का भी शिकार हुआ कांके डैम

कांके डैम का रातू रोड वाला इलाका सबसे घनी आबादी वाला है। इस इलाके में कांके डैम के किनारे का कैचमेंट और ग्रीनलैंड जमीन दलालों ने मजदूर वर्ग के लोगों को से बेच दिया और वो जैसे तैसे मकान बना कर इसमें बसते चले गये। ऐसे में रांची के विधायक और पूर्व नगर विकासमंत्री ने वोट बैंक के लिये इन्हें अवैध रूप से बसने से रोकने के बजाय रोड, बिजली, पानी तक उपलब्ध करा दिये।

जहां अतिक्रमण वहां कोइ नहीं देखने वाला

कांके डैम का दक्षिणी किनारा रातू रोड के समानांतर है। इन इलाकों में रातू रोड का इंद्रपुरी, सरोवर नगर, जनक नगर के सिरे जाकर मिलते हैं। इनमें सबसे हरा भरा और विविध प्राकृतिक संरचनाओं से समृद्ध इलाका सरोवर नगर का है। और प्रायः इधर कोई अफसर या मंत्री मुआयना करने नहीं आते हैं। जनक नगर के सिरे की ओर से दो नदियां कांके डैम में आकर मिलती हैं। पंडरा पुल के नीचे से गुजरने वाली नदी भी कांके डैम में आकर मिल जाती है। इस नदी पर भी विलुप्ति का खतरा है। इसे पंडरा बस्ती में ही रोक दिया गया है। यह नदी कांके डैम की मुख्य जलस्त्रोत है जिसके बारे में ग्रीन रिवोल्ट ने विस्तृत खबर प्रकाशित किया था।

कहां - कहां है अतिक्रमण?

कांके डैम की बनावट ऐसी है कि इसके उत्तरी किनारों की ओर कोई अतिक्रमण संभव नहीं है क्योंकि उस ओर लंबाई में बांध है जो नवासोसो गांव तक जाती है। लेकिन नवासोसो इलाके से लेकर कांके रोड के पॉश कॉलोनियों तक में अलग-अलग तरीके से अतिक्रमण है। नवासोसो में कांके डैम में मिलने वाली नदी के ऊपर बने पुल के पास डैम में ही दोमंजिले मकान और कुछ छोटे बड़े मकान एवं खटाल बना लिये गये हैं। वहीं सरोवर नगर से लेकर इंद्रपुरी तक ग्रीन लैंड और कैचमेंट तक में छिपुट अतिक्रमण है। वहीं कांके रोड में बड़ी बड़ी कॉलोनियां डैम के किनारे ही हैं और यहां डैम की एकड़ों जमीन बांडड्री कर घेर लेने की सूचना है जो पूरी तरह से कैचमेंट एरिया है जिसमें जल एकत्र होता है।डैम में समस्या अतिक्रमण के अलावा प्रदूषण और इसके खत्म हो चुके जलस्त्रोत हैं।

रांची की खुबसूरती, शान और रौनक रहे कांके डैम को बचाना जरूरी

बहुत कम शहरों में कांके डैम जैसा विशाल जलाशय मौजूद है। और कांके डैम को अगर गौर से देखें तो रांची शहर की खुबसूरती में चार चांद लगाने के साथ ही यह यहां के पर्यावरण को भी समृद्ध बनाता है। इसके एक सिरे पर रॉक गार्डेन की पहाड़िया हैं जिस पर चढ कर इस विशाल जलाशय का सुंदर मनोहारी अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन हाल के दशकों में इस डैम पर ग्रहण लग गया है। कभी साफ नीले जल वाले इस डैम का पानी अब शैवालों और जलकुंभियों के सड़ने से ज्यादतर समय हरा रहता है और इसके किनारों से बदबू आती है। इसके किनारों को सजाने लाइट बत्ती , घाट बनाने वाले ठेकों को काम तो खूब हुआ पर प्रदूषित डैम को साफ करने का काम कभी नहीं हुआ। यहीं कारण है कि कभी बहुतायत में छोटी झींगा मछली वाले इस डैम में अब कचड़ा खाने वाली तिलैपिया की भरमार है। अब सिर्फ जाड़ों में आने वाले प्रवासी पक्षी ही इसकी रौनक हैं

पौधारोपण से ज्यादा कारगर है बीजारोपण

अरिमर्दन सिंह

मानव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है स्वच्छ पर्यावरण के लिए भरपूर हरियाली का होना। अनादिकाल से ही पेड़ पौधों से मानव जाति का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है लेकिन इस सम्बन्ध पर अगर हम गहरी नज़र डालें तो पायेंगें कि पौधों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए मानव की अपरिहार्यता कभी नहीं रहीं जबकि मानव सहित सभी जन्तुओं के कल्पना पौधों और वनस्पतियों के बिना नहीं की जा सकती है क्योंकि कुदरत ने मानव के साथ ही अन्य जीवों द्वारा श्वसन क्रिया से बाहर छोड़ी गई गन्दी हवा (कार्बन डाइआक्साइड) को सोख कर हमारे श्वांस लेने के लिए आवश्यक प्राण वायु आक्सीजन तथा भोजन बनाने की क्षमता केवल हरे पेड़-पौधों को दी है जन्तुओ को नहीं। प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में पेड़-पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइआक्साइड गैस व पानी से अपना भोजन बनाने के साथ ही आक्सीजन मुक्त करते हैं, जो जीवन का आधार है।

वन क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों को मिलेगी गति और मजबूती

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयासों के साथ लक्षित कार्यक्रम भी चलाये गये लोगों को अधिकाधिक पौधारोपण के लिये प्रेरित करने व पेड़-पौधों के महत्व और पर्यावरण को स्वच्छ करने में उनके योगदान को भी बताया जाता रहा है लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य पौधारोपण की बजाय बीजारोपण, में लापरवाही के कारण वृक्षविहीन होती धरती को हरा भरा बनाने का हमारा कोई भी प्रयास अच्छी तरह रंग नहीं ला पा रहा हैं। हम पौधारोपण पर तो ध्यान दे रहे हैं मगर लम्बी आयु तक हरे भरे रहने वाले वृक्ष तैयार करने के लिए बीजारोपण करने पर शायद ही किसी का ध्यान हो और शायद इस कारण से भी स्थिति दिन प्रतिदिन बद्तर होती जा रही हैं ।

.....शेष पेज तीन पर

सीसीएल में मना विश्व पर्यावरण दिवस

- विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय जैव विविधता
- सीएमडी गोपाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन में कमांड क्षेत्रों में 84 लाख पौधारोपण किया जा चुका है।

संवाददाता रांची : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 05 जून को सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में आयोजित पर्यावरण कार्यक्रम में सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह एवं निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल ने सीसीएल मुख्यालय, रांची के प्रांगण में 'पर्यावरण ध्वज' को फहराया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष सहित सीसीएल कर्मियों एवं अन्य ने यह शपथ लिया कि प्राकृतिक वन, झील, नदी एवं वन्य प्राणियों के सरंक्षण एवं संर्वद्धन के लिये यथाशक्ति प्रयास करेंगे तथा जीवित प्राणियों के प्रति करूणा एवं दया का बर्ताव करेंगे।

सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह के कुशल मार्गदर्शन में कंपनी

कायाकल्प योजनाओं के अंतर्गत रांची सहित सभी कमांड क्षेत्रों में वृहद स्तर पर पौधारोपण लगातार करता रहता है और अब तक 84 लाख पौधारोपण किया जा चुका है।

निदेशक तकनीकी (संचालन)वी.के. श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी को प्रेरित करते हुये कहा कि अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि स्थान देना होगा ताकि हमारी अगली पीढ़ी पर्यावरण का लाभ ले सके।

निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह ने कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल का 'पर्यावरण संदेश' पढ़कर सभी को सुनाया एवं सभी से पर्यावरण में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिये प्रेरित करते हुये कहा कि हम सभी को योगदान किसी न किसी रूप में प्रकृति के लिए देना चाहिए। निदेशक (वित्त) श्री एन.के. अग्रवाल ने उपस्थित सभी कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को अपने जीवनकाल में अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए। हमारा मुख्य कार्य कोयला उद्योग है इस नाते हमारा कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सीसीएल इस दिशा में विभिन्न प्रयास करता आ रहा है। सीसीएल द्वारा सभी कमांड क्षेत्रों में वृहद स्तर पर पौधारोपण, ईको पार्क का विस्तार, धूल जनित प्रदूषण की रोकथाम, नवीनतम तकनीकी का उपयोग कर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सीसीएल में हर वर्ष पर्यावरण दिवस पर एक नया थीम लिया जाता है, इस वर्ष का थीम ''जैव विविधता'' है। जिसमें लुप्तप्राय पौधों एवं जन्तुओं की प्रजातियों तथा जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जैव- विविधता पर ध्यान केंद्रित करने और विलुप्त होने के कगार पर खड़े पौधों और जन्तुओं की प्रजातियों की रक्षा के लिए कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियां वैज्ञानिक अध्ययन कर रही हैं। कोल इंडिया ने 2019-20 के दौरान लगभग 19.7 लाख पौधे लगाए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 812 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है।

वर्तमान समय में सीसीएल प्रबंधन बच्चों के लिए 03 से 05 जून तक ऑनलाईन प्रतियोगिता (स्केचिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, क्वीज, स्लोगन, लेखन) का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस के अंतर्गत ई-मैगजीन एवं पर्यावरण संबंधित 'ऐप' का विमोचन सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह द्वारा किया जायेगा। इस अवसर पर सीसीएल ने फलदार पौधों का वितरण किया कार्यक्रम को सफल बनाने में विभागाध्यक्ष सौमित्र सिंह एवं उनकी टीम का सक्रिय योगदान से किया गया।

जीडीपी होगी गिरावट, पर कृषि में तीन प्रतिशत तक होगी की वृद्धि

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में सभी क्षेत्रों में गिरावट के बावजूद कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना जताई गई है।

भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में पहली तिमाही में 25 फीसदी की बड़ी गिरावट आ सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईडी) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-जून (पहली तिमाही) के दौरान कृषि क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में भारी गिरावट आएगी। यही नहीं बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना भी जल्द नहीं दिखती है। रिपोर्ट के अनुसार यह स्थिति अगले वित्त वर्ष में भी बनी रहने की आशंका है। एनसीएईडी ने यह रिपोर्ट 8 जून 2020 के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़े द इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में जारी की है।

एनवायरनमेंट परफॉरमेंस में भारत 168वें स्थान पर

एजेंसियां

येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 180 देशों के एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स 2020 में भारत को 168वां स्थान दिया गया है जोकि स्पष्ट तौर पर भारत में पर्यावरण की ख़राब दशा को प्रदर्शित करता है । भारत में पर्यावरण की जो दशा है उसकी स्थिति हाल ही में जारी एनवायरनमेंट परफॉरमेंस इंडेक्स 2020 से साफ हो जाती है इस इंडेक्स को येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है जिसमें 180 देशों को पर्यावरण के अलग-अलग संकेतकों के आधार पर रैंक किया गया है इस इंडेक्स में भारत को 168वें स्थान पर रखा गया है जोकि स्पष्ट तौर पर भारत में पर्यावरण की ख़राब दशा को प्रदर्शित करता है इस इंडेक्स में भारत को उसकी पर्यावरण सम्बन्धी परफॉरमेंस के लिए 100 में से 27.6 अंक दिए गए हैं जबकि इस इंडेक्स में 82.5 अंकों के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है वहीं 2018 में भारत को 177वां स्थान मिला थो जब 30.57 अंक अर्जित किये थे यह इंडेक्स पर्यावरण के 32 संकेतकों पर आधारित है जिसे 11 श्रेणियों में बांटा गया है इसके आधार पर 180 देशों को उनकी परफॉरमेंस के लिए अंक दिए गए हैं।

फिसड्डी रहे एशिया के मुल्क

इंडेक्स में भारत के साथ-साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन भी कोई ख़ास अच्छा नहीं रहो यदि भारत को देखें तो वो सिर्फ 11 देशों से आगे है जिसमें बुरुंडी, हैती, चाड, सोलोमन आइलैंड, मेडागास्कर, गिनी, आइवरी कोस्ट, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान, म्यांमार और लाइबेरिया शामिल हैं जबकि दक्षिण एशिया में भारत अफगानिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसियों से पीछे है स्पष्ट तौर पर भारत को यदि पर्यावरण के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को सुधारना है तो उसे सभी मोर्चों पर दोगुनी मेहनत करने की जरुरत है जिसके लिए हवा और पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है।

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गयी थी स्टेट ऑफ इंडियास एनवायरनमेंट 2020 नामक इस रिपोर्ट में भी भारत के सतत विकास के लक्ष्यों में पिछड़ने पर चिंता जताई थी इस रिपोर्ट के अनुसार अन्य दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति को ख़राब बताया गया था।

तो क्या सबसे गया गुजरा जानवर है मनुष्य ?

महात्मा गांधीः किसी देश के लोगों के व्यवहार के बारे में जानना हो तो पहले वहां के लोगों का पशु पक्षियों के प्रति व्यवहार को देखें

मनोरंजन सिंह

केरल के मल्लपुरम में हथिनी को फल में बम खिला कर मार दिया गया, सारे देश के जीवप्रेमी इससे आहत हैं। हथिनी गर्भवती थी और बम विस्फोट में उसके सूंड, जबड़े तो घायल हुये ही उसके पेट में भी जहरीले बारूद के अंश चले गये। वह जलन से तड़प कर एक तालाब में जा घुसी और वहीं उसके प्राण पखेरू उड़ गये। ये सिर्फ एक उदाहरण भर है सारे देश में जंगली या पालतू पशुओं के साथ ऐसी क्रूरता आम है। चुंकि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का समय है इस कारण से ऐसे क्रूर कारनामें ज्यादा संख्या में लाग देख रहे हैं और उनका विरोध भी हो रहा है।

मनुष्य खुद को सबसे विवेकशील और बुद्धीमान प्राणी कहता है और खुद को एक सामाजिक पशु मानता है, लेकिन हथिनी की क्रूरतापूर्ण हत्या ने मनुष्यों के एक सामाजिक पशु होने पर ही सवाल

उठा दिया है। हाल की पशुओं के प्रति कुछ क्रूर घटनाओं को हम देखें तो सबसे क्रूर और हिंसक पशु तो हम मनुष्य ही हैं। चीन के बाजारों से लेकर थाइलैंड में जिमने प्रकार के जानवरों को क्रूरता से मार कर खाया जाता है उसे देख सुन कर ही घिन आ जायेगी। चीन में गदहों की खाल से कोई सूप बनाते हैं और चीनियों ने सारे गधों को मार कर खा लिये अब वे पाकिस्तान से खाने के लिये गधे मंगा रहे हैं। भारत में केरल जानवरों के प्रति विभत्स घटनाओं और क्रूरता के लिये कुख्यात है। बकौल मेनका गांधी केरल का मल्लपुरम देश के सबसे हिसंक जिलों में से एक है। वहां जानवरों को बहुत ही बेरहमी से मजे के लिये भी मार डाला जाता है। मेनका गांधी ने बताया कि वहां एक मंदिर में हाथी को चारो पैर में मोटी जंजीरों से बांध कर रखा गया है और उसके रोज पीटा जाता है। हाल में ही सूचना मिली कि वह हाथी भी अब मारा गया। केरल में कुत्तों और सड़क पर घूमते अवारा जानवरों को मारने के लिये खाने में जहर मिला कर सड़क पर बिखरा देने की खबरें भी हैं। और वहां कुटीपाई खाने की भी संस्कृति है। कुटिपाई गर्भवती बकरी को मार कर उसके अजन्में बच्चे के मीट को कहते हैं।

केरल के अलावा सारे देश भर में हमारा बर्ताव नीरीह मूक पशुओं के प्रति बहुत ही क्रूरता भरा है। इंटरनेट पर कुत्तों को बेरहमी से मारने के हजारो वीडियो मिल जायेंगे जिन्हें देख कर आप सिहर उठेंगे और मनुष्य होने पर शर्म आने लगेगी। हाल ही में एक खबर आयी कि हिमाचल में किसी ने गाय को चारे में बम मिला कर देदिया जिससे उसका पूरा जबड़ा ही उड़ गया। आखिर इससे किसी को क्या प्राप्त होगा?

हर सप्ताह झारखंड में ही कई बड़े वाहन पकड़े जाते हैं जिसमें गोवंशियों की तस्करी हो रही होती है। जब भी पुलिस इन ट्रकों की जांच करती है तो उस एक ट्रक में क्षमता से अधिक गोवंशियों को ठूंस ठूंस कर रखा गया होता है और ये सारे गोवंशी बूचड़खाने को जा रहे होते हैं। अब यहां सवाल है कि इन गोवंशियों को कसाइयों के हाथों बेचता कौन है?

मनुष्य खुद को कितना भी विवेकशील कहे पर हमारा पशु पक्षियों, जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार हमें किसी हिंसक जानवर सा बनाता है।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

जानवरों से बदतर हो गये हम

आंध्र प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक बंधे हुये छोट से डॉगी को बेरहमी से एक आदमी मार कर उसकी हत्या कर देता है और उसे घसीट कर ले जाता है, उसे देश कर घर के लोग चीख पुकार मचा रहे हैं, पर वह आदमी कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। केरल के मल्लपुरम में एक हथिनी को बम खिला कर मारने की हृदयविदारक घटना से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि हिमाचल में किसी ने बम से गाय के जबड़े को उड़ा दिया। चीन में कोरोना पशु पक्षी, जानवरों के भक्षण से फैला और वहां के रेस्टोरेंट और होटलों में दुनिया भर के लोग तरह - तरह के जानवरों का मांस खाने के लालच में पहुंचते रहे हैं। और वहां पारंपरिक रूप से किसी जानवर को मार कर खाने की संस्कृति है। माना जा रहा है कि कोरोना भी चमगादड़ खाने से फैला?

आस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग में (जिसे षडयंत्र के तहत मनुष्यों का ही लगाया गया बताया गया है) लाखो पशु पक्षी जल कर मर गये। और वहां का पूरा इको सिस्टम बर्बाद हो गया।

ये सारे वाकये यही जता रहे हैं कि जीवों में सर्वोपरि मनुष्य जानवरों से भी बदतर और नीच हो चुका है। हम अपने ज्ञान बघारने में पशुओं को विवेकहीन, अज्ञानी और वनचर कह कर मनुष्यों से नीच बताते हैं, पर हकीकत में हमारा व्यवहार जंगली तो छोड़िये पालतू पशु पक्षियों के प्रति भी बहुत ही क्रूर और भयंकर है। हकीकत में तो किसी हिंसक क्रूर पशु की तरह का व्यवहार हम मनुष्यों का ही हो गया है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी देश को जानना हो तो पहले उस देश के लोगों का पशुपक्षियों जानवरों के प्रति व्यवहार कैसा है? ये देखना चाहिये।

इस कसौटी पर देखें तो हम भारतीयों ने भी कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है। केरल में हथिनी को अनानास में बम खिला कर मारना, गाय को बम खिला कर उसके जबड़े को उड़ा देना, कुतों को पीट पीट कर मार देना, बिल्ली को फांसी दे देना और सड़क पर घूमते पशुओं के साथ मजे के लिये अत्याचार भारत में होते हैं। जबकि हमारी संस्कृति सभी जीवों क लिये बराबरी का संदेश देती है।

एड्स मनुष्यों का रोग नहीं था यह अफ्रिका के ग्रीन मंकी में पाया जाता था, मनुष्यों ने ग्रीन मंकी के साथ भी संसर्ग का कुकर्म किया और आज तक एड्स ढो रहा है।

भारत में तेजी से घट है जल की उपलब्धता

भारत पहले से ही जल की उपलब्धता को लेकर तनाव की स्थिति में है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) द्वारा जारी किए गए एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस के अनुसार, भारत को दुनिया के 17 ''अत्यंत जल-तनावग्रस्त'' देशों में तेरहवें स्थान पर रखा गया है। भारत में बेसलाइन जल संकट ''बेहद उच्च'' स्तर पर पहुंच चुका है और हमारे बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। किसी भी क्षेत्र में ''जल तनाव'' तब उत्पन्न होता है जब पानी की मांग उपलब्ध मात्रा से अधिक होती है या उसकी गुणवत्ता कम होती है जिसके फलस्वरूप जल का प्रयोग नहीं हो पाता।

प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में घोषित किया है और ऐसे में देश के नीति निर्माताओं के लिए जल निश्चय ही एक सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। भारत में नदियों का एक विस्तृत नेटवर्क है, जो लगभग 20 नदी घाटियों के सहयोग से बनता है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु मिलकर हिमालय के जलग्रहण क्षेत्र से 40 प्रतिशत से अधिक उपयोग करने योग्य सतह-जल को समुद्र तक ले जाती हैं। मानव हस्तक्षेप के अलावा घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपयोगों के लिए जल की बढ़ती मांग ने इसकी उपलब्धता को प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश नदियों के प्रवाह क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है।

केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 1984-85 और 2014- 15 के बीच सिंधु नदी में पानी की मात्रा में 27.78 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की कमी आई है। यह कमी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक, कावेरी में कुल उपलब्ध पानी के बराबर है। ब्रह्मपुत्र के जल में 95.56 बीसीएम और गंगा में 15.5 बीसीएम की कमी मापी गई है। 2017 में जारी आंकड़ों से एक और परेशान करने वाला रुझान निकलकर सामने आता है। 2004-05 और 2014-15 के बीच, सिंधु के जलग्रहण क्षेत्र में 1 प्रतिशत, गंगा में 2.7 प्रतिशत और ब्रह्मपुत्र के जलग्रहण क्षेत्र में 0.6 प्रतिशत की कमी आई है। प्रति व्यक्ति सतह जल उपलब्धता भी 1951 के 5,200 घन मीटर से घटकर 2010 में 1,588 रह गई है।

हर हाल में बचाना होगा तालाबों को

पंकज चतुर्वेदी

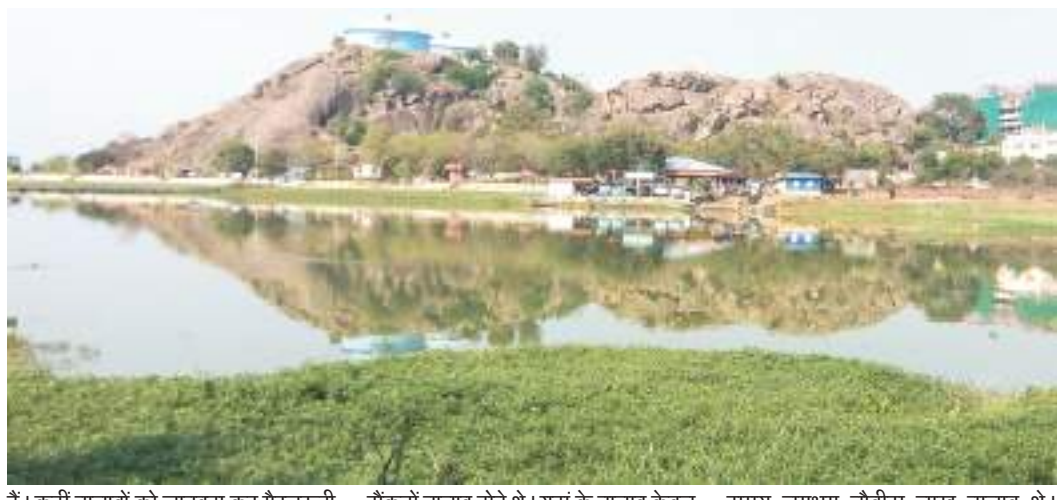

देश में एक सशक्त तालाब प्राधिकरण गठित हो, जो सबसे पहले देशभर की जल-निधियों का सर्वे करवा कर उनका मालिकाना हक राज्यों के माध्यम से अपने पास रखे, यानी तालाबों का राष्ट्रीयकरण हो। फिर तालाबों के संरक्षण, मरम्मत की व्यापक योजना बनाई जाए।

गांव में पानी के संकट से निपने का सबसे अच्छा उपाय तालाब है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश के बत्तीस फीसद हिस्से को पानी की किल्लत के लिए गर्मी के मौसम का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। बारहों महीने, तीसों दिन यहां 'जेठ' ही रहता है। सरकार संसद में बता चुकी है कि देश की ग्यारह फीसद आबादी साफ पीने के पानी से महरूम है। वहीं जिन इलाकों की जनता जुलाई-अगस्त में अतिवृष्टि के लिए हाय-हाय करती दिखती है, सितंबर आते-आते उसके नल सूख जाते हैं। बारिश से सड़क व नदियां उफनती हैं और पानी देखते ही देखते गायब हो जाता है।

इस पानी को सहेजने के लिए पारंपरिक स्रोत ताल-तलैया को तो सड़क, बाजार, कालोनी के कंक्रीट के जंगल खा गए। दूसरी तरफ यदि कुछ दशक पहले पलट कर देखें तो आज पानी के लिए परेशान हो रहे इलाके अपने स्थानीय स्रोतों की मदद से ही खेत और गले दोनों के लिए अफरात पानी जुटाते थे। एक दौर आया जब अंधाधुंध नलकूप लगाए जाने लगे, लेकिन जब तक संभलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

समाज को एक बार फिर तालाब, कुंए, बावड़ी जैसे बीती बात बन चुके जल-स्रोतों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर पीढ़ियों का अंतर सामने खड़ा है, पारंपरिक तालाबों की देखभाल करने वाले लोग किसी और काम में लग गए और अब तालाब सहेजने की परंपरा नदारद हो गई। यही नहीं, सरकार का भी कोई एक महकमा मुकम्मल नहीं है जो सिमटते तालाबों के दर्द का इलाज कर सके। तालाब कहीं कब्जे से, कहीं गंदगी से तो कहीं तकनीकी ज्ञान के अभाव से सूख रहे हैं। कहीं तालाबों को जानबूझ कर गैरजरूरी मानते हुए समेटा जा रहा है, तो कही उसके संसाधनों पर किसी एक ताकतवर का कब्जा है। ऐसे कई मसले हैं जो अलग-अलग विभागों, मंत्रालयों, मदों में बंट कर उलझे हुए हैं। देश के इतने बड़े प्राकृतिक संसाधन, जिसकी कीमत खरबों रुपए से भी अधिक है, के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र और ताकतवर प्राधिकरण की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है तालाब केवल इसलिए जरूरी नहीं हैं कि वे पारंपरिक जल स्रोत हैं, बल्कि तालाब पानी सहेजते हैं, भूजल का स्तर बनाए रखते हैं, धरती के बढ़ रहे तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तालाबों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। सन 1944 में गठित फेमिन इनक्वायरी कमीशन ने साफ निर्देश दिए थे कि आने वाले सालों में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए तालाब ही कारगर होंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि कमीशन की रिपोर्ट पर किसी ने गौर नहीं फरमाया और लालफीताशाही का शिकार हो गई।

आजादी के बाद इन पुश्तैनी तालाबों की देखरेख करना तो दूर, इनकी दुर्दशा होनी शुरू हो गई। चाहे कालाहांडी हो, बुंदेलखंड हो या फिर तेलंगाना, देश के जल-संकट वाले सभी इलाकों की कहानी एक ही है। इन सभी इलाकों में एक सदी पहले तक सैंकड़ों तालाब होते थे। यहां के तालाब केवल लोगों की प्यास ही नहीं बुझाते थे, बल्कि स्थानीय अर्थ व्यवस्था का मूल आधार भी होते थे। मछली, कमल गट्टा, सिंघाड़ा, कुम्हार के लिए चिकनी मिट्टी का स्रोत यही तालाब ही थे। तालाबों का पानी कुओं का जल स्तर बनाए रखने में सहायक होता था। लेकिन शहरीकरण की चपेट में लोग तालाबों को ही पी गए और अब पीने के पानी के लाले पड़ रहे हैं।

वैसे तो मुल्क के हर गांव-कस्बे के तालाब अपने समृद्ध अतीत और आधुनिकता की आंधी में बबार्दी की एक जैसी कहानी कहते हैं। जब पूरा देश पानी के लिए त्राहि-त्राहि करता है, तब उजाड़ पड़े तालाब एक उम्मीद की किरण की तरह होते हैं। इसलिए सवाल है कि तालाबों को बचाया कैसे जाए, जल के इस पारंपरिक स्रोत के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाएं। हालांकि जल विशेषज्ञों की ओर से यह सुझाव अक्सर आता रहा है कि पुराने तालाबों के संरक्षण और नए तालाब बनाने के लिए ह्यभारतीय तालाब प्राधिकरण' का गठन किया जाना चाहिए। जिन इलाकों में सालाना बारिश का औसत 750 से 1150 मिलीमीटर है, वहां नहरों की अपेक्षा तालाब से सिंचाई अधिक लाभप्रद होती है।

एक आंकड़े के अनुसार, भारत में आजादी के समय लगभग चौबीस लाख तालाब थे। अकेले मद्रास प्रेसीडेंसी में ही पचास हजार और मैसूर राज्य में उनतालीस हजार तालाब थे। लेकिन अब हमारी यह तालाब-संपदा अस्सी हजार पर सिमट गई है। देश भर में फैले तालाबों, बावड़ियों और पोखरों की 2001-02 में गिनती की गई थी। देश में इस तरह के जलाशयों की संख्या साढे पांच लाख से ज्यादा है, इसमें से करीब चार लाख सत्तर हजार जलाशय किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि करीब पंद्रह फीसद बेकार पड़े हैं, यानी आजादी के बाद देश में बीस लाख से ज्यादा तालाब खत्म हो गए। बीस लाख तालाब बनवाने का खर्च आज बीस लाख करोड़ से कम नहीं होगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में केंद्र सरकार ने जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाई थी। ग्यारहवीं योजना में काम शुरू भी हुआ। योजना को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी। लेकिन आज तक इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

तालाबों के विकास और संरक्षण में एक बड़ी समस्या इन पर कब्जे की सामने आई है। तालाबों पर कब्जे कर लेना आसान इसलिए है क्योंकि पूरे देश के तालाब अलग-अलग महकमों के पास हैं। जैसे राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत, मछली पालन, सिंचाई, स्थानीय निकाय, पर्यटन ..आदि। कहने की जरूरत नहीं है कि तालाबों को हड़पने की प्रक्रिया में स्थानीय असरदार लोगों और सरकारी कर्मचारी की भूमिका होती ही है। अभी तालाबों के कुछ मामले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पास हैं और चूंकि तालाबों के बारे में जानकारी देने का जिम्मा उसी विभाग के पास होता है, जिसकी मिली-भगत से उस की दुर्गति होती है, इसलिए हर जगह लीपापोती होती रहती है। आज जिस तरह जल संकट गहराता जा रहा है, जिस तरह सिंचाई व पेयजल की अरबों रुपए वाली योजनाएं पूरी तरह सफल नहीं रही हैं। तालाबों का सही इस्तेमाल कम लागत में बड़े परिणाम दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि देश में एक सशक्त तालाब प्राधिकरण गठित हो, जो सबसे पहले देशभर की जल-निधियों का सर्वे करवा कर उनका मालिकाना हक राज्यों के माध्यम से अपने पास रखे, यानी तालाबों का राष्ट्रीयकरण हो। फिर तालाबों के संरक्षण, मरम्मत की व्यापक योजना बनाई जाए।

हकीकत में तालाबों की सफाई और उन्हें गहरा करने का काम अधिक खर्चीला नहीं है, ना ही इसके लिए भारीभरकम मशीनों की जरूरत होती है। यह सर्वविदित है कि तालाबों में भरी गाद, सालों साल से सड़ रही पत्तियों और अन्य अपशिष्ट पदार्थो के कारण ही बनती है, जो उम्दा दर्जे की खाद है। रासायनिक खादों ने किस कदर जमीन को चौपट किया है, यह किसान जान चुके हैं और इसीलिए उनका रुख अब कंपोस्ट व अन्य देशी खादों की ओर है। यदि जल संकटग्रस्त इलाकों के सभी तालाबों को मौजूदा हालात में भी बचा लिया जाए तो वहां के हर इंच खेत को तर सिंचाई, हर कंठ को पानी और हजारों हाथों को रोजगार मिल सकता है। एक बार मरम्मत होने के बाद तालाबों के रखरखाव का काम समाज को सौंपा जाए, इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, मछली पालन सहकारी समितियां, पंचायत, गांवों की जल बिरादरी को शामिल किया जाए।

संकट में जीवनरेखा बनी कृषि

देविंदर शर्मा

अतीत में उठाए गए कदमों को गिनाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्यारह विशिष्ट उपाय किए हैं; इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के लिए जारी 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में किसानों की मदद करने के लिए बृहस्पतिवार को भी दो उपायों की घोषणा की थी। लेकिन इसमें संकट में फंसे किसानों के हाथों में सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं था। हालांकि इनमें से अधिकांश उपाय पहले से ही बजट प्रस्तावों में शामिल हैं।

सीतारमण ने कृषि विपणन को आसान बनाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा हटाने के लिए तीन उपायों की भी घोषणा की, यह एक ऐसा कदम है, जो प्रसंस्करण उद्योग और थोक व्यापार में मदद करेगा। असाधारण समय को छोड़कर, जब आपदा आती है या जब खराब होने वाली फसलों की कीमतें सौ फीसदी और अनाज की कीमतें पचास फीसदी अधिक हो जाएं, व्यापारी अब जमाखोरी नहीं कर सकेंगे। किसानों को अपनी उपज बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कई विकल्प प्रदान करने वाला एक केंद्रीय कानून और अनुबंध खेती की सुविधा प्रदान करने के लिए कानून शीघ्र ही लाया जाएगा। फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज शृंखला जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए,समुद्री और अंतर्देशीय (घरेलू) मत्स्यपालन के लिए ,डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य जारी योजनाओं के लिए , पशुओं के खुरपका तथा मुंहपका बीमारी की रोकथाम के लिए ,सभी पशुओ का सौ फीसदी टीकाकरण के लिये, औषधीय पौधों, मधु मक्खीपालन, सूक्ष्म खाद्य उद्यमों में पोषण आहार, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। बेशक ये महत्वपूर्ण उपाय हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, तथा किसानों, मछुआरों और दुग्ध उत्पादक किसानों की मदद करेंगे, पर ये ऐसे कदम हैं, जो दीर्घकालीन कृषि गतिविधियों में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

मौजूदा संकट के दौर में जब लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से ठप हैं, केवल कृषि ही जीवन-रेखा बनी हुई है। सही मायने में कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में अपनी छवि मजबूत की है। पर रेस्तरां और ढाबों के लगभग 50 दिनों से बंद होने के कारण शहरी मांग घट गई है, जिसका कृषि को भारी खामियाजा उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी इसने आपूर्ति जारी रखी है। खबरें हैं कि नियमित रूप से आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों को सड़कों पर दूध बहाना पड़ा, मुर्गियों को जिंदा जलाना पड़ा, फूलों के खेत फिर से जोतने पड़े, पशुओं के आगे सब्जियां फेंकनी पड़ीं और सभी फसलों की कीमत बाजार में लगभग न्यूनतम स्तर पर चली गई, क्योंकि आपूर्ति शृंखला नियमित रूप से बाधित हुई। अनुमानों के मुताबिक, सब्जी उत्पादकों को 25,000 करोड़ रुपये, दुग्ध उत्पादकों को 10,000 करोड़ रुपये तथा फूल उत्पादकों, नर्सरी वालों, फल उत्पादकों व मछुआरों को भारी नुकसान के अलावे पॉल्ट्री उद्योग को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सभी बाधाओं के बावजूद किसानों ने लगभग 10.6 करोड़ टन गेहूं की कटाई की है, खरीफ फसलों की पहले ही ज्यादा बुआई की है, और आने वाले हफ्तों में वे धान रोपाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र पहले से ही संकट में है, उम्मीद की जा रही थी कि तत्काल राहत पैकेज आंशिक रूप से उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करेगा, और बुवाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

यहां सरकार के लिए संकट में किसानों के साथ खड़े होने और ज्यादा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का अवसर था। किसानों को तत्काल राहत पैकेज की जरूरत है, और उनके हाथों में अधिक नकदी प्रदान करने से अधिक मांग पैदा करने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले भी, जब वित्त मंत्री ने किसानों और समाज के अन्य सीमांत वर्गों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, किसानों के लिए एकमात्र प्रतिबद्धता पीएम-किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की एक किस्त देना था, जो उनका बकाया ही था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण मिलता है। अप्रैल-जून तिमाही की पहली किस्त बकाया थी। दूसरे शब्दों में, किसान अब तक किसी भी प्रत्यक्ष समर्थन से वंचित हैं। मेरा प्रस्ताव है कि पीएम-किसान आवंटन में देरी किए बिना बटाईदार किसानों सहित प्रति किसान 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, किसानों को गेहूं की कटाई और खरीद के समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उन्हें देखते हुए उन्हें गेहूं खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाना चाहिए। यह देखते हुए, कि कई लाख प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में लौट आए हैं, कृषि को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अतिरिक्त कार्यबल को खेती में समायोजित किया जा सके।

यह महामारी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। कृषि को पुनर्जीवित करना और खेती को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना इस अभियान का आधार है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। यह दूसरे देशों से सबक लेने का भी वक्त है। अमेरिका ने किसानों से सीधे सब्जियां, फल और दूध खरीदने तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए तीन अरब डॉलर की मदद दी है। भारत में खराब होने वाली फसलों के लिए इसी तरह की रणनीति पर काम किया जा सकता है। यह वक्त सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाने का है, जिससे किसान लाभान्वित हों। आखिरकार, किसानों ने यह प्रदर्शित किया है कि इस कठिन समय में वे अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ हैं।

(लेखक कृषि नीति विशेषज्ञ हैं।)

एशियाई देशों में कॉलेस्ट्राल लेबल बढ़ रहा है, यूरोप में घट रहा है

एक नए अध्ययन के अनुसार पश्चिमी देशों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में - विशेष रूप से एशिया में, वैश्विक कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है। शोध में कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच करने के लिए 1980 से 2018 की अवधि के दौरान 200 देशों के, 39 साल तक के 10.26 करोड़ लोगों के आंकड़ों का उपयोग किया गया। अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में पता चला कि दुनिया भर में होने वाली लगभग 39 लाख मौतों के लिए उच्च कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार है। इनमें से आधी मौतें पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में होती हैं।

कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है। स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में जमा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल विभिन्न प्रकार का होता है। उच्च-घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एचडीएल) 'अच्छा' कोलेस्ट्रॉल, जो 1 मिमी / एल या उससे ऊपर होना चाहिए, अतिरिक्त 'खराब' कोलेस्ट्रॉल को हटाने से दिल के दौरे और स्ट्रोक के खिलाफ एक सुरक्षा होती है।

लॉकडाउन के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में 417.1 पीपीएम की रिकॉर्ड वृद्धि

दुनिया भर में लॉकडाउन के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है एनओएए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2020 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417.1 पीपीएम पर पहुंच गया थो

एनओएए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2020 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 417.1 पीपीएम पर पहुंच गया थो दुनिया भर में लॉकडाउन के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ रहा है यह तब है जब दुनिया भर में कोरोना संकट से निपटने के लिए पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन कर दिया गया थो इसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होना चौंका देने वाला है। गौरतलब है कि इससे पहले लॉकडाउन की वजह से दुनिया के कई देशों में प्रदूषण का स्तर कम होने की खबरें भी सामने आई थी।

घर लौटते मजदूर:क्या सकारात्मक स्वदेश' वापसी होगी?

सन 1960 के आसपास गावों से शहरों की ओर विस्थापन शुरू हो गया था। इसका कारण किसानों की कृषि में बढ़ती कठिनाइयां रही। दिनोंदिन बढ़ता कर्ज और जमींदारों और महाजनों का अत्याचार भी था।साथ ही गांधी ने स्वराज का जो सपना बुना था, उसका साकार न होना था।

कमल कुमार

हाल के दिनों में बहुत कोशिश की कि सामने मौजूद परिदृश्य से इतर कुछ सोचने की कोशिश करूं। लेकिन कभी मौजूदा दौर के संदर्भ से इतर कोई और बात आती भी तो वह फिर उसी में गुम हो जाती। सवाल है कि साईकिल, रिक्शा, ट्रक, आटो, ट्रैक्टर या पैदल सैकड़ों-हजारों किलोमीटर जाते हुए, बैल की जगह खुद को जोत कर परिवार के साथ अपने गांवों की ओर जाते, भूखे-प्यासे, रेल की पटरियों पर या दुर्घटनाओं में मरते प्रवासी श्रमिकों की खबरें, इनकी तस्वीरें क्या सिर्फ देखने और सुनने के लिए हैं। इन्हें देख कर क्या हमारे भीतर कुछ होता है? शायद नहीं! भीतर में 'मर गया है' कुछ, जो इंसानी था। ये श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक समीकरण को साधे रखती आधी से ज्यादा आबादी है जो हमारे उद्योगों की रीढ़ है। उद्योग बड़े हों या छोटे, स्वदेशी हों या न हों किसी ने किसी रूप में ये दुकानों, दफ्तरों, कंपनियों में होते ही है। अब इनका अपने गांवों में इस तरह लौटना कई सवाल खड़े करता है। इनके बिना उद्योगों का क्या होगा ? दूसरी तरफ इनका घर लौटना क्या 'सकारात्मक स्वदेश' की वापसी भी हो सकती है? क्या वहां वे सहजता से अपना गुजारा करने लायक कुछ कर सकेंगे?

इतिहास में जाएं तो भारत में आम जीवन में घुले-मिले लघु और कुटीर उद्योग जीवन निर्वाह के साधन थे। लेकिन बाद में अपने घरेलू उत्पादों की अपेक्षा विदेशों से आयात उत्पादों से बाजार सज गए। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ता गया। शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में आकर लोग ठहरते और काम-धंधा ढूंढ़ कर करने लगे। मुंबई में ह्यधारावी' के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली में यमुना पार झुग्गी-झोपड़ियों का एक शहर बन गया। इसके अलावा हर पॉश कालोनी से थोड़ी दूरी पर कहीं न कहीं ये लोग रहने लगे। घरेलू सहायता से लेकर दफ्तरों में छोटे-मोटे काम करने वाले, दिहाड़ी कमाने वाले, निर्माण कार्यों और उद्योगों से जुड़े मजदूर..! ये हमारी शहरी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का आधार बनते गए। लेकिन इनको जो आर्थिक सुविधाएं और अधिकार व्यवस्था से मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। जबकि इनका योगदान कल-पुर्जा उद्योगों से लेकिन विनिर्माण में और छोटे-बड़े सभी उद्योगों में बहुत बड़ा है। देश को अब समझ आया है कि ये प्रवासी श्रमिक इस समय सत्तर करोड़ के आसपास है, जो छोटे-मोटे कारोबार, फल-सब्जी वाले, रेहड़ी-पटरी वाले, मैकेनिक, दर्जी, ब्यूटी-पार्लर के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

अब वे अपने गांव लौट रहे हैं। गांवों में सड़के हैं, बिजली है, गैस है, ई-कॉमर्स और ब्राडबैंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये गांवों में लौट कर फिर से एक नया जीवन का सपना लेकर लौट रहे हैं। कभी शहरों में वापस न आने का और वहीं से काम करने का। लेकिन क्या उनका यह सपना पूरा होगा? आज भी गांवों की वास्तविक तस्वीर कई बार डरा देती है। बहरहाल, काश विपदा में एक अवसर देखा जाता और गांधी के सपने को पूरा करने की कोशिश की जाती। लौटे हुए प्रवासी श्रमिक अपने-अपने क्षेत्र में किए गए काम को बखूबी कर सकते हैं। दूसरी ओर छोटे और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। पर अब क्रम को उलटना होगा। पहले ये गांवों से शहर आते थे, अब शहरों से इनके पास जाना होगा। इनके उत्पाद को सही तरीके से बाजार तक ले जाना होगा। साथ ही जिन उद्योगों में हम सक्षम हैं, उनका आयात भी रोकना होगा। चीनी समान ने किस तरह से हमारे लघु, कुटीर उद्योगों को नष्ट किया है, इसका अनुमान लगाइए कि दिवाली के लिए गणेश, लक्ष्मी इत्यादि की मूर्तियां हमारे बाजार में पटी पड़ी होती हैं। सस्ती होती हैं, इसलिए लोग इन्हें खरीदते हैं। दीए हो या बिजली का समान या सजावटी लाइटें।

अब तक अपने यहां लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं देने और विदेशों पर निर्भरता ने देश की हालत को सुधरने नहीं दिया। जबकि यह क्षेत्र न केवल स्थानीय लोगों और मजदूरों की रोजी-रोटी का नियमित साधन बन सकता है, बल्कि इससे देश की आत्मनिर्भरता की राह खुलेगी। आत्मनिर्भरता केवल नारा देने से नहीं आती। इसके लिए स्वदेशी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने की ईमानदार कोशिश करनी होगी। मुश्किल यह है कि स्वदेशी का महिमामंडन तो बहुत किया जाता है, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अपने पांव पसारने की भूमिका बनाना क्या दशार्ता है? इनका विस्तार स्थानीय और छोटे कारोबारियों को कितने दिन खड़ा रहने देगा? लगभग सभी क्षेत्र में लागू होने वाली नई नीतियां देश में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बनाएगी और अर्थव्यवस्था के केंद्र को उनके ही इर्द-गिर्द समेटेगी। इससे किसका भला होगा?

भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा: हेमन्त सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले धरती आबा ने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। उनके साहस, समर्पण और बलिदान प्रत्येक भारतीय को सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथलेश ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों ने भी भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

तालाबों के कायाकल्प के लिए पंजाब ने प्रस्तुत की अपनी कार्य योजना

पंजाब के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय द्वारा तालाबों के कायाकल्प के लिए कार्य योजना प्रस्तुत कर दी गई है। इस योजना के अनुसार पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग एवं ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने कुल 15,466 ग्रामीण और 249 शहरी तालाबों की पहचान की है। जिनका पुनरोद्धार किया जाना है। यह कार्य योजना एनजीटी के 10 मई 2019 को दिए आदेश के अनुसार तैयार की गई है। इस आदेश में एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने क्षेत्र में मौजूद सभी जल स्रोतों की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा था। साथ ही मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए थे।

रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट प्लांटों की कमी है। जिसके चलते तालाब अपशिष्ट जल के निपटान का केंद्र बनते जा रहे हैं।

रेल सुरक्षा बल और सुइसा पोस्ट ने किया योग शिविर का आयोजन

रांचीः 04जून को रेल सुरक्षा बल रांची पोस्ट तथा सुइसा पोस्ट द्वारा निशुल्क योगा शिविर का आयोजन सुबह 06:30 बजे से 07:45 बजे तक किया गया` जिसमे रांची रेल मंडल के रेल सुरक्षा बल के अधिकारीयों एवं कर्मचरियों ने हिस्सा लिया ।

कोरेना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन किया गया हैं, ऐसे स्थिति में रेल सुरक्षा बल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती हैं। स्टेशन, स्टेशन परिसर तथा रेल सीमा के अंतर्गत सभी जगहों पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं सुरक्षा प्रदान करना होता हैं। दिन भर की थकान तथा तनाव से मुक्त होने के लिए योगा एक सर्वोत्तम उपाय है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योगा शिविर का आयोजन किया गया ।

पौधारोपण से ज्यादा कारगर है बीजारोपण

.....पेज एक का शेष

अगर हम बीज से पेड़-पौधों के बनने और उगने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर एक नजर डाले तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकेगी कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम दीर्घायु वृक्षों का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें` ज्यादातर पेड़-पौधों की शुरूआत एक बीज से होती हैं` पेड़-पौधों में बीज के बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज के अन्दर सुप्तावस्था में रहता है` बीज के अन्दर स्थित भ्रूण तब तक इस सुप्तावस्था में रहता है, जब तक उसे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जिसमें पर्याप्त नमी और तापमान प्रमुख है, न मिल जाये और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले बीज का कवच भेद कर मूलांकुर, जिससे मूल जड़ विकसित होती है, बाहर निकलता है और यदि उसे उपयुक्त माध्यम मिलता है तो वही जड़ बढ़कर मूसला जड़ के रूप में अपने को स्थापित कर लेती है और पानी तथा खनिज लवणों का जड़ की सतह पर विकसित मूल रोमों द्वारा अवशोषण शुरु कर देती है। भ्रूण की शुरूआती वृद्धि के लिए प्रायः बीज में पहले से ही आवश्यक भोजन संचित रहता है` एक बार पानी और खनिज लवणों के अवशोषण की व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही भ्रूण का प्रांकुर या प्रारोह जिससे तना एवं शाखाएं आदि विकसित होती हैं, बाहर निकलता है और पौधे की सामान्य वृद्धि शुरु हो जाती है ।

यद्यपि सूर्य का प्रकाश और हवा तो पेड़-पौधों को सामान्यतया उपलब्ध रहती हैं,पर पानी की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण पौधों का प्रकृति से संघर्ष शुरु हो जाता है और जहाँ जैसी परिस्थितियां होती है, उनसे संघर्ष मे सफल रहने पर ही वह पौधा जीवित बच पाता है और उसका आकार-प्रकार तथा जीवन चक्र किसी स्थान विशेष पर पायी जाने वाली वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार ही होता है` यह संघर्ष अंकुरण की शुरुआत से लेकर आगे हमेशा चलता रहता है ।

पौधे जहाँ उगे हों वहाँ भूमि की ऊपरी सतहों में पानी की कमी होने पर पौधे इसे दो तरह से व्यवस्थित करते हैं । एक तो अपनी प्रमुख जड़, जिसे मूसला जड़ या टैप रूट भी कहा जाता है और जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा मे यानी नीचे की ओर बढ़ती है, पौधे उसे जमीन की उस गहराई तक बढ़ाकर ले जाने का प्रयास करते हैं जहाँ से उनको उनकी जरुरत के अनुरुप पानी का अवशोषण किया जा सके दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत पौधें अपने तने एवं पत्तियों की सतह से हो रही पानी की हानि (वाष्पोत्सर्जन) को कम से कम करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए पौधा स्थानीय जलवायु के अनुरूप ऊपर उतना ही बढ़ता है जितना कि आवश्यक पानी उसे जड़ों से मिलता रहता हैं । इस प्रकार पानी की प्राप्ति एवं खर्च में एक तारतम्य बना रहता है और पौधा बढ़ता रहता है । वहीं वृक्ष चूँकि आकार-प्रकार में काफी बड़े होते है और कई वर्षो तक जीवित रहते हैं । अतः इन्हें रोजाना काफी पानी की आवश्यकता के साथ-साथ जमीन में उसे स्थापित कर संभाले रखने एवं आंधी तूफान से बचाये रखने हेतु मजबूत और अत्यधिक विकसित जड़ तंत्र की आवश्यकता होती है। सीधे बीजों से उपजे वृक्षों की मूसला जड़ काफी विकसित, मजबूत एवं काफी गहराई तक जाती है` साथ ही इन जड़ों की शाखाएं चारों तरफ फैल कर मजबूती से वृक्ष को स्थापित करने के साथ ही पानी एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने का दायित्व भी निभाती हैं अपनी मजबूत मूसला जड. के साथ ही अत्यधिक विकसित जड़ तंत्र के कारण ही ये बड़े वृक्ष का आकार लेकर अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं और आंधी तूफान में जल्दी नहीं गिरते और पर्यावरण मे अपनी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार सीधे बीज से उगाये गए पौधे अपनी मूसला जड़ द्वारा जमीन में मजबूती से स्थापित होने के साथ ही पानी की उपलब्धता के साथ-साथ बढ़ते हैं और पानी की कमी से उनके सूख जाने का खतरा बहुत कम होता हैं । अच्छे खाद-पानी के साथ बीजों से उगे यह पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं ।

अब जरा वृक्षारोपण की खातिर नर्सरी में पौधे तैयार करने हेतु आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर नजर डाली जाये। पौधों के अंकुरण के लिए यहाँ भी बीजों को पहले प्रायः जमीन में बोया जाता है लेकिन उनके थोड़ा बड़ा होने पर ही उन्हें उखाड़कर मिट्टी से भरी पॉलिथीन की थैलियों में लगा दिया जाता है। मगर पौधों को लगाने से पहले उनकी मूसला जड़ नीचे से को काट दिया जाता है ताकि वह नीचे कम वृद्धि करें तथा पालीथीन के अन्दर ही जिन नर्सरी में पोलीथीन के थैलों में मिट्टी भर कर बीज बोया जाता है वहां भी उनके उगने के थोड़े समय बाद उनकी थैली के बाहरबढ़कर निकली जड़ों, जिनमें मूसला जड़ भी शामिल होती है, को काट दिया जाता है। नर्सरी में पौधों को जल्दी-जल्दी पानी देने के साथ ही कई बार उसका स्थान बदला जाता है और हर बार उसकी नीचे बढ़ी व थैली के बाहर आयी जड़ों को काट दिया जाता है । इस प्रकार पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण पौधा नर्सरी में ऊपर तो बढ़ता है पर उसकी जड़ पॉलीथीन के साइज के हिसाब से काट कर हर बार सीमित कर दी जाती है और एक या दो वर्ष में इस तरह से पौधे ऊपर तो कई फीट तक बड़े कर लिये जाते है पर उनकी जड़ की लम्बाई काट कर छोटी कर उतनी ही बनाये रखी जाती है। फिर बाद में ले जाकर उन्हें किसी स्थान पर रोपित कर दिया जाता है । चूँकि नई जगह पर पौधे को अक्सर नर्सरी जितना पानी नहीं मिल पाता है अतः पौधा पानी की कमी को पूरा करने के लिये अपना पूरा जोर लगा देता है । एक ओर जहाँ वह अपनी ज्यादातर पत्तियों को सूखाकर गिरा देता हैं, वहीं जमीन से ज्यादा से ज्यादा पानी सोखने के लिये जड़ से नई शाखाएं विकसित करता है लेकिन यह जड़े जमीन में बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। अब चूँकि पौधे की मूसला जड़ पहले से ही काटी जा चुकी है और उसकी जगह उतनी मजबूत जड़ फिर से नही बन पाने के कारण पौधा जमीन की ऊपरी परतों से तो पानी खींच लेता है पर गहरी परतों से पानी सोखने मे पूरी तरह सफल नहीं हो पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक पौधे को या तो वर्षा का जल या सिंचाई द्वारा दिया गया पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है तब तक तो वह जीवित रहता है और धीरे-धीरे वृद्धि करता है, लेकिन मौसम शुष्क होने तथा गर्मी बढ़ने पर पानी की उपलब्धता काफी कम हो जाती है । इस समय पौधा केवल जमीन की ऊपरी पर्तो में उपलब्ध पानी ही सोख पाता है, नीचे से नही, क्योंकि इनमे मूसला जड़ पूर्व में काट दिये जाने के कारण उतनी विकसित नहीं हो पाती है । मौसम अत्यधिक शुष्क होने तथा प्रचण्ड गर्मी के कारण इन पौधों के उपरी भागों से उड़ने वाले पानी तथा पौधों की जड़ों से सोखे जाने वाले पानी के बीच संतुलन विगड़ जाता है और पौधा एक तरह से डिहाईड्रेशन की अवस्था में पहुंचकर अन्ततः मर जाता हैं इस तरह रोपित किये गये पौधों की मृत्यु दर गर्म व सूखे मौसम के कारण बहुत ज्यादा होती है ।

वहीं बीज से उगा पौधा विपरीत परिस्थितियां आने पर भी अपनी मूसला जड़ के माध्यम से जमीन की निचली पर्तों से पानी सोखकर पौधे के खुले भागों से पानी के नुकसान व जमीन से पानी की प्राप्ति के बीच संतुलन बनाये रखता है और अपने को सूखने से बचाये रखने में सफल रहता है । बीजारोपण में बेहद कम लागत के साथ ही उन्हें लाने ले जाने में खर्च होने वाले भाड़े के साथ ही श्रम की भी बचत होती है तथा बीजों को इकट्ठा करने में गामीण क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है।

पहले बड़े-बड़े बागों तथा नहरों व सड़कों के किनारे फलदार एवं अन्य उपयोगी वृक्षों जैसे-आम, महुआ, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, पाकर, गूलर, सेमल, शीशम, चिलबिल इमली, कैथा, बेल, आँवला आदि की भरपूर जैव विविधता मौजूद रहती थी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र की आबादी की विभिन्न आवश्यकतायें पूरी होती थी बल्कि इससे पशु-पक्षियों के लिए वर्ष में अधिकांश समय में कुछ न कुछ खाने की उपलब्धता के साथ ही उन्हें परिवार बढ़ाने एवं विषम वातावरणीय परिस्थितियों- सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचने हेतु विशिष्ट परिवेश भी उपलब्ध होता था। ये वृक्ष विशालकाय होने के साथ-साथ सैकड़ो वर्षो तक जीवित रहते थे और टिकाऊ एवं अच्छा पर्यावरण बनाये रखने में काफी सहायक होते थे । आज नये राजमार्ग बनाने, उन्हें चौड़ा करने के साथ तेज शहरीकरण व औधोगीकरण तथा बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए नई कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए हरे-भरे और पुराने बड़े वृक्षों की कटान तो बढ़ती जा रही है पर उनकी जगह उस तरह के पेड़ हम नहीं तैयार कर पा रहें हैं यद्यपि दिनों दिन कम होती जा रही वर्षा के साथ छोटे-बड़े अन्य कारणों से ऐसा हो सकता है पर बुजुर्गों का मानना है कि अन्य क्षेत्रों की तरह वृक्ष तैयार करने के लिये अधिकांशतः बीजारोपण के बजाय पौधारोपड़ का शार्टकट अपनाना भी इसका प्रमुख कारण है ।

अतः वर्तमान परिस्थितियों में जब वर्षा की मात्रा हर साल धीरे-धीरे कम होती जा रही है, हमें वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये पौधारोपड़ से ज्यादा बीजारोपण पर ध्यान देना होगा। तभी इस दिशा में किए गए प्रयासों से टिकाऊ पर्यावरण विकसित किया जा सकेगा।

लेखक अपर महानिदशक, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, रांची हैं

फूलगोभी के खेती में बोरोन के प्रयोग की आवश्यकता

डॉ अरविन्द कुमार

फसल में पौधों को बड़ा होने में कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो पौधों में कई तरह के रोग लग जाते हैं. जिससे फसल खराब हो जाती है. फूलगोभी के पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के समूह में बोरान एवं मॉलीब्लेडिनम एक प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व है।

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा वैज्ञानिक डॉ अरविन्द कुमार बताते हैं कि शोध सर्वे में झारखण्ड के कुल भोगौलिक क्षेत्र के 45 प्रतिशत भूमि में उपलब्ध बोरोन की कमी पाई गई है. प्रदेश के सरायकेला, पलामू, लोहरदग्गा, पूर्वी सिंहभूम एवं लातेहार जिले के कुल भोगौलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भूमि में उपलब्ध बोरोन की कमी पाई गई है. जबकि अन्य जिले में भी इसकी कमी का स्तर 20-45 प्रतिशत तक पाया गया है। झारखण्ड की लाल एवं लेटेराईट भूमि में बोरोन की काफी कमी देखी गयी है. प्रदेश की राजधानी रांची एवं इसके आसपास क्षेत्रों में सब्जी की खेती खासकर फूलगोभी की खेती सालोभर की जाती है. डॉ अरविन्द कुमार बताते हैं कि फूलगोभी की खड़ी फसल में पत्तियों का मूडना, तना में खोखलापन, फल का छोटा होना और भूरापन या ब्राउनिंग होना बोरोन जेसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है. फूलगोभी में बोरॉन की कमी दूर करने के लिये बुवाई के समय खेत में अच्छे ढंग से सड़ी कम्पोस्ट खाद तथा 10 से 15 किलो प्रति हेक्टर की दर से बोरेक्स उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में बुवाई के 10 दिन बाद 14 किलो प्रति हेक्टर की दर से बोरेक्स उर्वरक या 9 किलो प्रति हेक्टर की दर से बोरिक एसिड उर्वरक पौधों के चारों ओर डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए।

खड़ी फसल में इसके कमी के लक्षण दिखने पर निदान हेतु पर्णीय छिड़काव के लिए 0.2 प्रतिशत बोरेक्स के साथ 0.3 प्रतिशत बुझा चुना का 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए या 0.125 प्रतिशत बोरिक एसिड, 1 मि. ली. टीपाल एवं 12 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10-12 दिनों के अंतर पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए।

सीएमपीडीआई में विश्व पर्यावरण दिवस-2020 मनाया गया

संवाददाता रांची : सीएमपीडीआई परिसर में निदेशक (तकनीकी), मुख्य सतर्कता अधिकारी, क्षेत्रीय संस्थान-3 के क्षेत्रीय निदेशक, सभी विभागाध्यक्षों, जेसीसी एवं सीएमओएआई के प्रतिनिधियों तथा मुख्यालय/क्षेत्रीय संस्थान-3 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस-2020 मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने पर्यावरण झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलवाई।

इस मौके पर एस सरन ने कहा कि कोविद-19 महामारी प्रकृति के साथ हमारे दुविधापूर्ण संबंध की एक कड़ी याद दिलाता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि वन्यजीवों का नुकसान एवं वनों की कटाई संक्रामक रोगों में वृद्धि करते हैं। हमारे इको-सिस्टम में बदलाव के कारण, प्रकृति ने अब दुनिया को मजबूत संकेत देना शुरू कर दिया है। अत्यधिक गर्मी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव, बाढ़, सुखा, लगातार चक्रवात कृषि, मानव एवं सम्पत्ति पर प्रभाव डाल रहा है। अब समय आ गया है कि प्रकृति के संदेश को समझा जाए और उसी के अनुरूप कार्य किया जाए। पारिस्थितिकी और जैव विविधता में परिवर्तन का यह उपयुक्त समय है और संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष के लिए इस विषय को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए चुना है।आगे उन्होंने कहा कि एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकास को सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोयला खनन के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता की बहाली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रतिशत वृक्षारोपण से आगे बढ़ने की जरूरत है और जैव विविधता पर सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाने होंगे।

इस अवसर पर सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/ईएस) के0के0 मिश्रा, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0के0 गोमास्ता, मुख्य सतर्कता अधिकारी सुमीत कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार, महाप्रबंधक (पर्यावरण) अभिजीत सिन्हा, जेसीसी सदस्य तथा सीएमओएआई के प्रतिनिधियों ने पौधा लगाया। इस अवसर पर अध्यक्ष, कोल इंडिया द्वारा जारी पर्यावरण संदेश पढ़कर सुनाया गया।

पर्यावरण को लेकर आज पूरे विश्व में चर्चा: मुख्यमंत्री

- रांची डोरंडा वन भवन में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री
- पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और जागरूक रहने की आवश्यकता
- प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रदेश की पहचान

रांची : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रकृति के आंचल में बसा प्रदेश है। यहां के हरे-भरे जंगल, खेत, नदी-नाले एवं प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रदेश की पहचान है। इन्हीं प्रकृतिक संपदाओं के दृष्टिगत इस प्रदेश को झारखंड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में हमसबों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और जागरूक होने की आवश्यकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज वन भवन, डोरंडा, रांची के परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं।

बायोडायवर्सिटी की परिकल्पना को साकार करना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोडायवर्सिटी सरकार की परिकल्पना है। हमसबों को मिलकर इस परिकल्पना को मूर्त रूप देना है। उन्होंने कहा कि हमारे आने वाले पीढ़ी को भी हम हरा-भरा प्रदेश सौपें यह हमसभी की जिम्मेदारी है। हमारा झारखंड प्रदेश जितना हरा-भरा रहेगा उतना ही खुशहाल जिंदगी झारखंड वासियों की होगी। वैसे भी झारखंड के लोग सदैव प्रकृति प्रेमी रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पूर्व में पर्यावरण के साथ काफी खिलवाड़ किया गया है।

आज संकल्प लेने का दिन : मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इस परिसर में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर पौधारोपण करें और हरे-भरे झारखंड के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों से भी पौधारोपण करने की अपील की।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शशि नंद कुलियार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री एके रस्तोगी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजीव लोचन बक्शी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

एसोचैम का वर्चुअल मीट ऑन "टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट पोस्ट कोविड-19" संपन्न

संवाददाता रांची : अब हम एक ऐसे वक्त में हैं जिसे कु द ही समय बाद "कोविद-19 के बाद की दुनिया " के रूप में जाना जायेगा । संभवतः अब हम प्रौद्योगिकी को एक ऐसे साधन के रूप में देखेंगे जिसमें उसकी भूमिका सिर्फ व्यावसायिक आचरण और उपभोक्ता पर ही केंद्रित नहीं होगी बल्कि कोविड-19 संकट से उबरने के बाद हमारा ध्यान इस ओर ज्यादा होगा कि प्राद्योगिकी समाज में जीवित रहने, स्वस्थ रहने और पर्यावरण को बेहतर बनोने में ज्यादा उपयोगी होगी । आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी का लक्ष्य और उसकी प्राथमिकता बिल्कुल ही अलग रूप में दिखेगी। एसोचैम एक जिम्मेदार चैंबर है जो इसे पर्यावरण की चिंता को भी पहचानता है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही एसोचैम ने नॉलेज मैनेजमेंट वर्चुअल मीट ऑन "टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट पोस्ट कोविड-19 युग" जैसा महत्वपुर्ण आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत भरत जायसवाल क्षेत्रीय निदेशक, एसोचैम के स्वागत भाषण से किया गया। इस आयोजन में उद्घाटन भाषण पर्यावरणविद् विधायक और भूतपूर्व मंत्री, झारखंड सरयू राय,ने दिया। उन्होंने स्वच्छ पर्यावरण पर अपने विचार दिए और नदियों को साफ करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रदूषित ना करने के लिए कहा, क्योंकि नदी हर मानसून के मौसम में खुद को साफ करती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए लाभ के लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिए और पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रौद्योगिकी द्वारा बनाए गए प्रदूषण को केवल प्रौद्योगिकी द्वारा साफ किया जा सकता है। मनु सेठ, स्पीकिंग मिंडज़ इंक ने सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी और प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव समुदाय, उद्योग और समाज पर पड़ता है और हमें तय करना है कि भारतीय समाज के लिए उनका लाभ कैसे उठाते हैं? श्रीमती नमिता बांका, संस्थापक और एमडी बंका बिजोलो लिमिटेड ने जल और स्वच्छता उद्योग में हरित प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने का सुझाव दिया।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए: डॉ. जेरेमी विलियम्स, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, जायद विश्वविद्यालय, दुबई, यूएई ने शुद्ध शून्य प्रभाव के लिए पेरिस अनुपालन और कॉर्पोरेट रणनीति पर अपने विचार दिये वहीं ी केपटाउन में समावेशी शिक्षा के मुख्य निदेशक श्री सिगमनी नाइकर ने प्रौद्योगिकी पर अपना विचार रखे ।

सीसीएल ने बांटे श्रमिक ट्रेन में प्रवासी मजदूरों के बीच फूड पैकेट

संवाददाता : सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड(सीसीएल) ने 1200 फूड पैकेट और 1200 पानी बोतल रेलवे प्रबंधन को सौंपा। सभी फूड पैकेट और पानी बोतल आज स्पेशल श्रमिक ट्रेन से यात्रा कर रहे प्रवासी मज़दूरों सहित बच्चों के बीच वितरण किया जायेगा। सीसीएल लगातार विगत दिनों से स्पेशल श्रमिक ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रमिक एवं उनके परिवार के बीच फूड पैकेट और पेयजल का वितरण कर रहा है। अभी तक 10 हजार से अधिक फूड पैकेट एवं पानी बोतल वितरित किया जा चुका है। केंद्र सरकार देश के दूरदराज के इलाकों में फंसे मजदूरों एवं उनके परिवार को उनके घर पहुंचाने के लिए 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन चला रही है । सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक गोपाल सिंह के मार्गदर्शन में सीसीएल इस कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तन्मयता से कर रहा है । सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन के नेतृत्व में सीसीएल द्वारा सीएसआर के अंतर्गत राँची, हटिया और बरकाकाना रेलवे स्टेशन से गुजर रही 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को फुड पैकेट एवं पानी का वितरण कर उन्हें सहायता पहुंचा रहे है ।

फोटो न्यूज

आइये अपने हिस्से का पेड़ लगायें : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची ,डोरंडा में पौधा लगाया और कहा कि आइये हम सब अपने हिस्से का पेड़ लगायें और उसे सींचे

चमकदार त्वचा के लिए कैसा हो आहार?

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

आहार हमारे शरीर के साथ हमारे त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने में मदद करता है। बाज़ार में बहुत प्रकार के सौन्दर्य प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे हमारी खुबसूरती कुछ समय के लिए अच्छी हो जाती है परन्तु प्रोडक्ट्स का असर खत्म होने पर फिर से त्वचा की चमक चली जाती है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराते हैं तो उससे भी सिर्फ कुछ समय के लिए ही त्वचा में निखार आता है। अगर हम अपने खाने के तरीके को ही सुधार लें और पौष्टिक आहार लें तो हमारे त्वचा अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनाती है।

अगर हमें स्वस्थ त्वचा चाहिए तो हमें समय पर खाना चाहिए, तेल मसाले का कम प्रयोग करना चाहिए, फ़ास्ट फ़ूड कम खाना चाहिए । आइए जानते हैं कुछ खाद्य-पदार्थ जो त्वचा के लिए काफी लाभदायक है।

✓हरी पत्तेदार सब्जियां- हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन, मिनरल और आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा को चमकदार बनाता है।

✓प्रोबायोटिक- दही और छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को चमकदार बनाता है।

✓डार्क चॉकलेट - इनमे एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो हमारे त्वचा को लिए काफी लाभदायक है।

✓ हाइड्रेट रहे- पानी काफी मात्रा में पीते रहना चाहिए जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और शरीर को डिटौक्स भी करता है।

✓फलो का सेवन करें- फलों में विटामिन्स, खनिज, एंटी-ऑक्सीडेंट और नेचुरल शुगर होता है जो त्वचा को स्वस्थ रखता है।

✓ग्रीन टी- ग्रीन टी में मैजूद एंटी-ऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को मारता है और त्वचा को जवान और खूबसूरत रखता है।

✓विटामीन सी- विटामिन सी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है इसलिए संतरा, मौसंबी, नींबू आदि का प्रयोग रोज करना चाहिए।

✓मछली-मछली में ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होता है जो त्वचा को चमकदार बनाने में सहायक है।

✓सीडस और नट्स- इनमें भी ओमेगा थ्री फैटी एसिड काफी होता है ।चिया सीड,अलसी , अखरोट आदि का प्रयोग भी त्वचा के लिए फायदेमंद है।

हमारा खान -पान सही होने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और साथ साथ ये हमारे चेहरे को भी चमकदार बनाता है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

भारत में पर्यावरण सुरक्षा को दी जानी चाहिए प्राथमिकता

भारत को पर्यावरण से जुड़े सभी प्रमुख पांच मापदंडों पर क्षेत्रीय औसत से भी कम अंक मिले हैं जिसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और पेयजल, हैवी मेटल्स और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं। इससे पहले डाउन टू अर्थ द्वारा जारी रिपोर्ट में भी इन मुद्दों पर भारत के गिरते स्तर पर चिंता जताई थी यही वजह है कि देश में इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की जरुरत है

इनके अलावा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित मापदंडों पर भी भारत का प्रदर्शन कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा थो यदि क्लाइमेट चेंज को देखें तो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद भारत का दूसरा स्थान थो इस इंडेक्स में पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज में 50.6 आंक प्राप्त किये थे साथ ही इस इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज पर दस साल की तुलनात्मक प्रगति रिपोर्ट भी दिखाती है कि भारत जलवायु संबंधी मापदंडों पर पिछड़ रहा है। इस इंडेक्स में जलवायु परिवर्तन का प्रदर्शन आठ संकेतकों पर आधारित है जिसमें उत्सर्जन में हो रही वृद्धि दर; चार ग्रीनहाउस गैसों और एक प्रदूषक की वृद्धि दर; भूमि आच्छादन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि दर; ग्रीनहाउस गैस की तीव्रता और वृद्धि दर; एवं प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल हैं रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में ब्लैक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में इसका कुल स्कोर 2.9 अंक नीचे चला गया है।

रांची रेल मंडल में विश्व पर्यावरण दिवस मना

संवाददाता रांची : 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल में विभिन्न स्थानों पर" विश्व पर्यावरण दिवस" के उपलक्ष में वृक्षारोपण तथा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ के द्वारा हटिया स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के बगल के मैदान में वृक्षारोपण किया गया तथा पर्यावरण का संरक्षण करने हेतु शपथ ली गई ।

सर्वो रांची की अध्यक्षा श्रीमती रूबी अम्बष्ठ ने सर्वो द्वारा संचालित हटिया स्थित लिटिल हार्ट स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण किया इस अवसर पर सर्वो की उपाध्यक्षा श्रीमती नीता यादव, उपाध्यक्षा श्रीमती अनुपमा पंडित, सर्वो की अन्य पदाधिकारी एवं सदस्याएं उपस्थित थी।। रेल कर्मचारियों के स्कूली बच्चों के लिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने अपने घर से ही इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंडल कार्यालय के कार्य स्थलों में, रेलवे कॉलोनी में विशेष साफ-सफाई की गई एवं हटिया स्थित कोचिंग डिपो में वृक्षारोपण किया गया। रांची मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए विविध

कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) श्री अजीत सिंह यादव, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) श्री एम एम पंडित एवं मंडल के सभी शाखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

क्या मुश्किल है वायु प्रदूषण से निबटना ?

एजेंसियां :जनवरी 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), वायु गुणवत्ता प्रबंधन व अनुपालन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाने की दिशा में एक कदम है। कार्यक्रम के तहत, पीएम 10 और पीएम 2.5 के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा नहीं करने वाले 122 शहरों की पहचान ''गैर-प्राप्ति'' शहरों के रूप में की गई है। इनमें से लगभग 60 प्रतिशत शहर गंगा नदी के मैदानी हिस्से में हैं। बाकी अन्य छह प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में हैं। इनमें से लगभग 70 फीसदी शहरों की आबादी दस लाख से भी कम है।

अनपरा, गजरौला और रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और उनकी आबादी क्रमशः 18,000, 55,045, 1,90,000 है। इसी तरह, बिहार में गया व मुजफ्फरपुर, दोनों की आबादी 5 लाख से कम है। ऐसे शहरी केंद्रों में, स्थानीय कार्रवाई से वायु प्रदूषण से उपजे स्थानीय जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर उनके बड़े प्रभाव क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है, तो इन स्थानों की हवा को एक बिंदु से परे साफ नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित गैर-प्राप्ति शहर डाउनविंड इलाकों (वैसे शहर जिनकी ओर हवा का बहाव हो) और क्षेत्रों की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

अतः इन उदाहरणों से साफ है कि हमें अपना ध्यान बड़े एयरशेडों पर लगाने की जरूरत है। लेकिन यह कहना आसान है और करना उतना ही कठिन। एयरशेड कई राज्यों के अधिकार क्षेत्रों और शासन प्रणालियों का एक जटिल मिश्रण है। क्षेत्रीय एयरशेड को चिन्हित करने और पूरे राज्य में कार्रवाई, निगरानी और अनुपालन का एक सामान्य और सामंजस्यपूर्ण ढांचा बनाने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। वैश्विक स्तर पर, सरकारें इस चुनौती का जवाब ढूंढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ''ट्रांसबाउंड्री'' वायु प्रदूषण से संबंधित अंतर-सरकारी संधियां और समझौते हैं। उदाहरण के लिए लांग-रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन समझौता। भारत के एनसीएपी ने एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण व अंतर-राज्य समन्वय के विचार को मान्यता दी है। एनसीएपी का मानना है कि एक क्षेत्रीय योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें क्षेत्रीय स्रोत आवंटनों के अध्ययनों से लिए गए इनपुट शामिल हैं। इसमें कई ऐसे उपायों को सूचीबद्ध किया है जो कि प्रकृति में क्षेत्रीय हैं और कई संस्थाओं के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यह लगातार बाढ़ रहे वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए आवश्यक शासकीय ढांचे और अंतर-राज्य सहयोग को मजबूत करेगा। अब समय है जब वायु प्रदूषण रोकथाम की प्रक्रिया में एक बदलाव की शुरूआत की जाए ताकि राज्य सरकारों की सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय कार्रवाई के लिए व्यापक और अधिक प्रभावी भागीदारी हो सके।

मेरे बचपन का साइकिल वाला प्यार ले डूबा कोरोना

शशी भूषण कुमार

वक्त बदला और जीवनशैली बदलती चली गयी। हम वो बचपन में जीते थे जहाँ कही घूमने की बात हो तो साइकल की सवारी ही दिल में गजब का सुकून भर देता था ,और तो और वो बचपन भी क्या गजब का रोमांच भर देता था जब हम बच्चे उन बच्चों को ज़्यादा सम्मान से देखा करते थे जो साइकिल चलाना जानते थे और जो नहीं भी जानते वो अक्सर बच्चे साइकिल सीखने के लिए लालायित रहते थे। उन बच्चों में मेरा शौक भी कुछ वैसी ही था,जो झट- पट सीख के हवाओं से बातें करने को आतुर हुवा करती थी, क्यूंकि मेरे लिए घर में पिताजी की वही साइकिल उस दौर में सम्मान हुआ करता था जो आज के दौर की मोटरसाइकिलों में बुलेट, पैशन प्रो , स्प्लेंडर या अपाची का हुआ करता है . क्युंकि कभी शादियों में दूल्हे को उपहार स्वरूप मिलने वाली जिस साइकिल पर बैठना ही सम्मान का विषय हुआ करता था।

बचपने में पिताजी की साइकिल कम ही सीखने के लिए बच्चों को मिलती थी और ये बात मेरे लिए भी लागू होती है । शायद इसके पीछे घर के बड़े चोट लगने के डर से साइकिल देने से मना कर देने से हो। जब घरों में रिश्तेदार आते थे तो मेरी ख्वाहिशे उनके माध्यम से पूरी होती. या साइकिल गेहूं पीसने या सरसो का तेल निकलवाने के लिए गठरी लादकर ले जाने के लिए ही सही कभी-कभार

मिल जाती थी। पिताजी के दफ्तर जाने के पहले उनका साइकिल को कपडे से पोछने वाला कहानी बस यह है कि इस बहाने मै साइकिल को घर से बाहर थोडा डोर सकूँ ,यह सब सारा स्वांग इसलिए की घरवाले मुझे इस काबिल समझ कर साइकिल चलाने की स्वतंत्रता दे सके। आखिरकार यह सब मेहनत मुझे विश्वासी होने के लायक बनाया और फिर मोहल्ले तक आजादी मिली फिर वही साइकिल मेरे लिए 8 वीं कक्षा में स्कूल जाने के लिए रथ माफिक बन बैठा।

अब क्या हुआ एटलस कंपनी के साथ ?

अब 21 वी सदी का दौर साइकिल पर बैठना प्रतिष्ठा के पतन के सूचक की तरह हो गया। धीरे-धीरे सड़कों पर साइकिलों की संख्या कम होती चली जा रही है। इसकोरोना ने बहुत कुछ को डुबोया पर 3 जून को देश की बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी एटलस साइकिल ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। विश्व साइकिल दिवस के दिन कंपनी ने ये फैसला किया है, जिससे 1000 मजदूरों की नौकरी पर संकट आ गया है।

एटलस ने कभी परचम लहराया था

हालांकि एक ऐसा भी समय था जब कम्पनी ने सालाना 40 लाख साइकिल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बढ़ती सम्पन्नता और मोटरसाइकिल के दौड़ में काफी समय पहले से ही साइकिल कम्पनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। एटलस साइकिल कंपनी की स्थापना देश के विभाजन के बाद करांची से आए जानकी दास कपूर ने 1951 में की थी। पहले ही साल इस कंपनी ने रिकॉर्ड 12000 साइकिलों का निर्माण किया था। 1965 तक आते-आते एटलस कम्पनी देश की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। इस कंपनी को भारत में पहली रेसिंग साइकिल बनाने का श्रेय भी हासिल है। एटलस कंपनी द्वारा सन 1958 में ही साइकिलों की पहली खेप के निर्यात का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बाद में एटलस कम्पनी को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट की मान्यता भी मिली। एटलस साइकिल कंपनी ने अपने कार्य के दम पर इटली का गोल्ड मर्करी इंटरनैशनल अवॉर्ड भी जीता लेकिन ये सब अब सिर्फ स्वर्णिम इतिहास ही बनकर रह गया है। प्रतिस्पर्धा और कोरोना के कारण हुई दयनीय आर्थिक स्थिति से एटलस कम्पनी को बंद करने का निर्णय लिया गया।

एटलस साइकिल कम्पनी को भले ही अब बंद कर दिया गया हो लेकिन 90 के दशक के लगभग हर भारतीय के जहन में रची-बसी एटलस साइकिल की छवि शायद ही फर्राटा मारना बंद करे।

खेतों में उड़तीं तितलियां मन को खूब भाती हैं

सुरेशचंद्र रोहरा

तितलियां आज भी मन को मोहती हैं। आज भी जब अचानक दिख जाती हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। मगर अब यह बात तल्खी के साथ महसूस होती है कि कभी मैं तितलियों के संसार के निकट था... कितना पास! आज कितना दूर हूं। मैं हरी घास पर बैठ गया।

रंग-बिरंगी तितलियां ही कभी मेरा संसार थीं। नन्ही-सी तितली, उड़ती जाती। मैं उसे पकड़ने की प्रत्याशा में पीछे दौड़ता चला जाता। न घर की सुध, न मां की। आंखों के आगे पीली तितली है, मैं मुग्ध भाव से तकता हूं। तब तितली जीवन का सर्वस्व थी और भागते-भागते जब हाथ आते-आते फिर उड़ जाती, तो निराशा का घटाटोप अंधेरा छा जाता। उस उम्र में सिर्फ इतना ही समझ आ पाता कि तितली को पकड़ना था। तितली उड़ गई। कुछ पलों की मायूसी, फिर किसी और तितली पर नजर गई तो उसके पीछे दौड़ पड़ा। और नहीं तो किसी और खेल में मग्न हो गया।

नन्ही-सी तितली नन्हा-सा मैं। तब कितनी पास थी तितलियां। आंखों के आगे प्यारी, सलोनी, आकर्षक चित्र बिखेरतीं तितलियां कई-कई स्वरूप में। तब मैं तितलियों के बिल्कुल पास था, आंखों, हृदय के पास। याद है कि घर के पास खाली मैदान था। हरी-हरी घास और मैं तितलियां ढूंढ़ रहा था। नन्हे-नन्हे हाथों से पकड़ कर, नन्ही हथेली पर रखने की इच्छा लेकर दौड़ता था। इस बात का भी खयाल नहीं कि अगर किसी तितली को पकड़ते हुए अंगुलियां जरा-सी लापरवाह हो गईं तो तितली की जान चली जाएगी!

बस ये था कि कैसे तितली को साथ ले लूं तितली के साथ हो जाऊं! कैसा निश्छल भाव था। तितलियों का संसार था और उस संसार में मैं था। सोचता था कि काश मेरे भी पंख होते और मैं भी तितली रानी के साथ उड़-उड़ जाता। यह दृश्य मनो-मस्तिष्क में छप गया है, अंकित हो गया है, जो अब कभी मिट नहीं सकता।

नन्हे हाथ-पैर लिए प्रकृति की गोद में तितलियों का मोहक संसार अद्भुत था। इसका शब्दों में भला कैसे वर्णन किया जा सकता है! अनिर्वचनीय! ऐसी अनुभूति होती थी मानो बस यही मेरा संसार है। कई बार तो कोई और खेल खेल रहा होता और इस बीच आसपास किसी खूबसूरत तितली पर नजर पड़ जाती तो सब छोड़ कर तितली की ओर दौड़ पड़ता। लेकिन तितली की अपनी गति थी। जरा-सी आहट महसूस हुई नहीं कि उड़ कर लहराती हुई कहीं और निकल चली! कई बार लहराती हुई मंडराने लगती थीं। इसके बगैर कोई कल्पना अधूरी थी। नीली, पीली, काली, सफेद तितलियां, जब दिखतीं तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता। कोई साथी जब किसी तितली को नन्हे-नन्हे हाथों, उंगलियों से पकड़ लेता तो लगता कि ओह! और मैं भी आशा से भरा तितली पकड़ने दौड़ पड़ता। चाहत थी कि तितली मेरे हाथ में हो, मेरी जेब में या बस्ते में! कैसा अद्भुत समां और दृश्य था। तितली मनमोहक थी, नन्हे मन और विचारों में अपनी अद्भुत छटा से आकर्षण का अनोखा वितान रचती हुई, जिससे बाहर निकल सकना असंभव था।

सुबह-सवेरे तितलियां हरी घास में उड़ती हुई दिखतीं, मैं पहुंच जाता, एक बड़ी प्रत्याशा लिए कि आज तो जरूर एक तितली मेरे हाथों में होगी, मगर अक्सर निराशा ही हाथ आती। नन्ही-सी परी, नन्हा- सा मैं, टुकुर -टुकुर तितली को ढूंढ़ता और जब दिख जाती तो चेहरा अनोखी आभा से खिल उठता। मैं पीछे-पीछे दौड़ता तितली तो तितली है, उसके पास पंख है। वह अभी यहां, अभी वहां। मैं पास जाता, वह शायद समझ जाती और उड़-उड़ दूर चली जाती। झपट्टा मारता, मगर हाथ में नहीं आती..! यह आशा और निराशा का खेल चलता रहता।

सोचता, मेरे साथी कैसे तितली को पकड़ लेते हैं! मैं क्यों नहीं पकड़ पाता? निराशा होती, मगर मैं फिर दौड़ता-फिरता कि कभी तो मेरे हाथ भी आ जाएगी। मन में यही कल्पना होती- काश! मेरे भी पंख होते तो तुरंत पास पहुंच जाताङ्क साथ उड़ता और अठखेलियां करता। तितली बहुत- बहुत पास थी। हरित घास के मैदान में उड़ती रहती और मैं उन्हें ढूंढ़ता रहता। यह संसार कितना अद्भुत और हृदयग्राही था। प्रेम और निश्चल से आपूरित यह अनुभूति होती। यही हमारा जीवन है। यही जीवन का सार है।

तितलियां आज भी मन को मोहती हैं। आज भी जब अचानक दिख जाती हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। मगर अब यह बात तल्खी के साथ महसूस होती है कि कभी मैं तितलियों के संसार के निकट था। कितना पास! आज कितना दूर हूं। मैं हरी घास पर बैठ गया। तितलियां पास थीं, हृदय प्रफुल्लित हो उठा। मैं तितलियों की उड़ान देख रहा था। यह तितली। वह तितली। अब हाथ बढ़ा कर पकड़ने की भूल और कोशिश नहीं करता। स्मरण हो आते हैं वे बचपन के दिन, जब एक अदद तितली के लिए मैदान में जाने कितने चक्कर लगा लेता था। यह अनुभूति बेहद सुखकारक है।

वे दिन जो बीत गए, जिनकी स्मृति शेष है, आंखों के आगे वह भला आजीवन कैसे मिटाई जा सकती है। तितली से मुलाकात, मानो प्रकृति से मुलाकात। आज जब मैं खड़ा-खड़ा तितलियों को ढूंढ़ और निहार रहा था, प्रतीत हो रहा था कि मैं कितनी दूर चला गया हूं। काश, मैं नन्हा बालक हो जाऊं और फिर उनके पीछे दौडूं और प्रकृति के एकाकार हो जाऊं। यही चाहत लेकर मैं घास पर आराम से पसर गया। सुबह-सवेरे का वक्त है। घास के विस्तारित वितान पर तितलियां हैं और सिर्फ मैं हूं।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in

Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511

Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm

SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।